

ललितपुर की घटना को लेकर एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।

ललितपुर जिले के महारौली पुलिस थाने में चोरी के शक में महिला की पुलिस द्वारा पिटाई की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

एनएचआरसी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस देकर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। दोषी पुलिसकर्मियों पर लिए गये एक्शन और पीड़िता को राहत देने के बारे में जानकारी मांगी है। आयोग ने नोटिस में कहा कि यदि इस बारे में मीडिया में आई खबरों में सत्यता है तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। पुलिस अधिकारी और उसका परिवार अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर शारीरिक चोट पहुंचाने और क्रूरता के दोषी हैं।

आयोग ने मीडिया की उन खबरों का संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया था कि 2

मई को पुलिस अधिकारी की पत्नी ने चोरी के शक में घरेलू काम करती महिला को घर में कैद कर लिया था। उसके पुलिस अधिकारी पति ने महिला इंस्पेक्टर को साथ

लाकर पीड़िता से चोरी के सामान के बारे में पूछताछ की। उसने पीड़िता की बुरी तरह पिटाई की और चोरी कबूल करने के लिए उस

मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

चोरी के शक में पुलिस ने थाने में निर्ममता से की थी पिटाई

पर पानी की धार छोड़ी और विजली के शॉक दिए। जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया पुलिस अधिकारी ने पीड़िता को थाने पर बुलाया और इस प्रकरण को पीड़िता और उसके पति के बीच का विवाद करार देने लगे।

दोनों के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई कर दी। आयोग ने इस पूरे प्रकरण को वेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी से चार हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में अवगत कराने का आदेश दिया है।

मानवाधिकार आयोग ने बिहार की जेलों की क्षमता, सुरक्षा बढ़ाने आदि की आवश्यकता जतायी

<https://www.prabhasakshi.com/national/human-rights-commission-express-concerns-over-bihar-jail>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार की जेलों में कैदियों को रखने की क्षमता बढ़ाए जाने, सुरक्षा का चाक चौबंद प्रबंध करने तथा जेल परिसर के भीतर स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता जतायी है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य बीन एम. मूले के नेतृत्व में आयोग की एक टीम ने छपरा जेल और पटना के बेउर जेल का निरीक्षण करने के बाद शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी बंद हैं, इसे देखते हुए संबंधित अधिकारियों से काराओं की क्षमता बढ़ाने को कहा है।

मूले ने कहा कि निरीक्षण के दौरान महिला कैदियों के चर्म रोग से ग्रस्त होने की बात सामने आयी है, ऐसे में जेल परिसर में स्वच्छता पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश जेल प्रशासन को दिया गया है। मूले ने कहा कि जेल के भीतर प्रतिबंधित सामग्री पहुंचने पर रोक के लिए कर्मियों की संख्या बढ़ाए जाने, सीसीटीवी कैमरा एवं फ्लड लाइट और अधिक संख्या में लगाए जाने की आवश्यकता जतायी है।

मानवाधिकार आयोग की यह टीम छपरा जेल में बंद वैशाली जिला निवासी चंदन शाह (35) नामक विचाराधीन कैदी की 2020 में स्पीट सेवन से मौत होने के मामले की जांच के लिए बिहार आयी थी। इस अवसर पर मौजूद बिहार के कारा महानिरीक्षक मनेश मीणा ने बताया कि प्रदेश में कुल 59 कारा हैं जिनकी क्षमता 47,750 कैदियों को रखने की है पर वर्तमान में इन जेलों में करीब 64 हजार कैदी बंद हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में पांच अन्य कारा लगभग बनकर तैयार है तथा 9 अन्य काराओं के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण मामला प्रक्रियाधीन है।

एनएचआरसी ने अंतरधार्मिक विवाह के कारण दलित युवक की हत्या मामले में लिया संज्ञान, Telangana government को जारी किया नोटिस

<https://samacharnama.com/states/telangana-news/NHRC-takes-cognizance-of-Dalit-youths-murder-case-due-to/cid7343694.htm>

दरअसल लड़की का परिवार उसके अंतर-धार्मिक संबंध और शादी के खिलाफ था। हालांकि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर देखा है कि कानून के किसी भी डर के बिना व्यापक सार्वजनिक स्थानों में इस तरह के जघन्य अपराध अराजकता की ओर इशारा करते हैं और मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन हैं। आयोग ने मुख्य सचिव को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है कि क्या अंतरजातीय या अंतर धर्म विवाह के मामलों में ऑनर किलिंग की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार की कोई नीति है।

डीजीपी को मामले में जांच की वर्तमान स्थिति, पीड़ित की पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उन्हें दी गई किसी भी राहत की जानकारी देने के लिए कहा गया है। साथ ही आयोग यह भी जानना चाहेगा कि क्या इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई चूक हुई है, यदि हां, तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

यूपी सरकार को NHRC ने दिया नोटिस, पुलिस ने महिला संग की थी मारपीट, 4 हफ्ते देना होगा जवाब

<https://upkiran.org/nhrc-gave-notice-to-the-up-government-the-police-had-assaulted-the-woman-will-have-to-answer-for-4-weeks/>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने ललितपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा एक महिला से कथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

एनएचआरसी (NHRC) ने जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई कार्रवाई और अधिकारियों द्वारा पीड़ित को दी गई किसी भी राहत पर भी रिपोर्ट मांगी है। कथित तौर पर, महिला एक पुलिस अधिकारी के आवास पर घरेलू सहायिका के रूप में काम कर रही थी और घर में चोरी के आरोप में उसे पीटा गया था।

NHRC ने एक बयान में कहा "आयोग ने पाया है कि मीडिया रिपोर्ट की सामग्री यदि सही है, तो पीड़ित के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। पुलिस अधिकारी और उसके परिवार ने न केवल अपने पद का दुरुपयोग किया है बल्कि पीड़ित को शारीरिक यातना और क्रूरता के अधीन भी किया है।"

कथित तौर पर, 2 मई को, पीड़िता को एक महिला निरीक्षक के साथ आए पुलिस अधिकारी की पत्नी ने एक कमरे में बंद कर दिया और घर में चोरी के संबंध में उससे पूछताछ शुरू कर दी। (NHRC)

NHRC ने कहा "उसे बेरहमी से मारने के अलावा, उन्होंने उसे आरोपों को स्वीकार करने के लिए पानी और बिजली के झटके भी दिए। बाद में, यह महसूस करते हुए कि मामला विवाद में बदल सकता है, उसे महरौली पुलिस स्टेशन बुलाया गया जहां पुलिस कर्मियों ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। मामले को उसके पति के साथ विवाद के रूप में और शांति भंग करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू की।"

NHRC notice to UP govt for police brutality

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Uttar Pradesh government over the reported stripping and assault of a woman by police personnel in Lalitpur. Taking suo motu cognisance of the incident, NHRC has called for a detailed report in the matter within four weeks. It has also sought a report on action taken against the responsible police officer and any relief granted to the victim by the authorities.

Reportedly, on May 2, the victim working as a domestic help at the residence of a police officer, was beaten on the allegations of a theft in the house.

"The Commission has observed that the contents of the media reports, if true, raise serious issues of violation of human rights to the victim. The officer and his family have not only misused their position but also subjected the victim to physical torture and cruelty", said the commission in a statement.

AGENCIES

NHRC notice to MP govt, DGP over 'detention' of 4 juveniles

NEW DELHI: The NHRC has sent notices to the Madhya Pradesh government and the state's police chief over a report that four juveniles have been illegally detained in police custody in Tikamgarh district on suspicion of theft. The news report reveals the juveniles have been "chained by the police" and there are injuries on their bodies indicating they are "being subjected to torture by the police", the NHRC said.

{ KHEVRAJPUR MULTIPLE MURDERS }

Gang rape, other IPC sections added to FIR

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

PRAYAGRAJ : The Prayagraj police have added the relevant sections of the Indian Penal Code for gang rape in the case of the murder of five members of a family at Khevrajpur village of Tharwai development block of the district last month, an official said. The step has been taken two weeks after the incident.

The sections that have been added in the FIR now include Section 376D (gang rape), 396 (murder during dacoity), 120 B (party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death), 201 (causing disappearance of evidence of offence) and 436 (mischief by fire or explosive substance with intent to destroy house, etc).

Prayagraj senior superintendent of police Ajay Kumar said, "During interrogation of seven persons of an interstate gang of looters arrested for the crime on May 4, they had confessed to have gang raped two women, too, during the incident."

"After the slide and swab report from Forensic Science Lab, Phaphamau on Friday con-

DNA samples to be collected

The Prayagraj district police have got permission from the district court to take DNA samples from the seven arrested members of the inter-state gang and match it with not just the multiple murders at Khevrajpur and Gohri villages, but also in Andhi village and Nawabganj areas of the dis-

trict where, too, the modus operandi of the criminals seems similar to the ones seen at Khevrajpur and Gohri, police said.

"This process will begin on May 9 with the drawing of blood of the accused gang members for their DNA," Prayagraj SSP Ajay Kumar said.

firmed gang rape, relevant sections of the crime have also now been added to the FIR registered in connection with the crime," the SSP added.

The blood-soaked bodies of a cattle trader, his wife, daughter, daughter-in-law and one-year-old granddaughter were found in their house on April 23. They had been battered to death. The house was also found set on fire. A four-year-old girl was the only survivor in the house.

The only son of the cattle trader, who was not at home at the time of the incident, had lodged an FIR in connection with the incident. Despite his suspicion of sexual assault on

his wife and his sister, the police at the time had registered an FIR only under the IPC section 302 for murder. The non-inclusion of rape sections in the FIR in the first instance had drawn flak from representatives of various political parties.

The Trinamool Congress (TMC) had alleged a "massive cover-up" by Prayagraj police after a five-member delegation of the party had visited Khevrajpur village and met the kin of the victims on April 25.

The TMC had also written to the National Human Rights Commission (NHRC) and met its chairman on April 29 in this regard.

ललितपुर की घटना को लेकर एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

■ सहारा न्यूज ब्यूरो

लखनऊ।

ललितपुर जिले के महरौली पुलिस थाने में चोरी के शक में महिला की पुलिस द्वारा पिटाई की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है।

एनएचआरसी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस देकर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। दोषी पुलिसकर्मियों पर लिए गये एक्शन और पीड़िता को राहत देने के बारे में जानकारी मांगी है। आयोग ने नोटिस में कहा कि यदि इस बारे में मीडिया में आई खबरों में सत्यता है तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। पुलिस अधिकारी और उसका परिवार अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर शारीरिक चोट पहुंचाने और क्रूरता के दोषी हैं।

आयोग ने मीडिया की उन खबरों का संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया था कि 2

मई को पुलिस अधिकारी की पत्नी ने चोरी के शक में घरेलू काम करने वाली महिला को घर में कैदकर लिया था। उसके पुलिस अधिकारी पति ने महिला इंस्पेक्टर को साथ

लाकर पीड़िता से चोरी के सामान के बारे में पूछताछ की। उसने पीड़िता की बुरी तरह पिटाई की और चोरी कबूल करने के लिए उस

मुख्य सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

चोरी के शक में पुलिस ने थाने में निर्ममता से की थी पिटाई

पर पानी की धार छोड़ी और विजली के शॉक दिए। जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया पुलिस अधिकारी ने पीड़िता को थाने पर बुलाया और इस प्रकरण को पीड़िता और उसके पति के बीच का विवाद करार देने लगे।

दोनों के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई कर दी। आयोग ने इस पूरे प्रकरण को वेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी से चार हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में अवगत कराने का आदेश दिया है।

महरौनी थाने में महिला के उत्पीड़न पर मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

आरोपितों पर **कार्रवाई** व पीड़िता की मदद के संबंध में रिपोर्ट तलब

राब्यू, लखनऊ: ललितपुर के पाली थाने में इंस्पेक्टर द्वारा किशोरी से दुष्कर्म की तरह ही इस जिले के महरौनी थाना पुलिस ने भी खाकी पर दाग लगाए। आरोप है कि सिपाही अंशू पटेल और उपनिरीक्षक पारुल चंदेल ने चोरी के शक में अंशू के घर काम करने वाली सहायिका को पहले घर में निर्वस्त्र कर पीटा। फिर थाने में लाकर उत्पीड़न किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में पूरी रिपोर्ट मांगी है।

मानवाधिकार आयोग की ओर से शनिवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक, ललितपुर के महरौनी थाने में पुलिस कर्मियों ने घर में चोरी करने के शक पर महिला

● ललितपुर की सनसनीखेज घटना पर मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस

का हद दर्जे का उत्पीड़न किया गया। उसे बेरहमी से बेल्ट से पीटा। आयोग ने नोटिस में दो मई की घटना का उल्लेख किया है कि पुलिस कर्मी ने महिला पुलिस अफसर के साथ पहले घर में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा। पानी की बौछार छोड़ने के साथ उसे करंट लगाया गया। उसके बाद थाने लाकर मारपीट की गई। फिर उसका पति से विवाद बताकर शांति भंग में कार्रवाई कर दी गई।

आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी से पूछा है कि आरोपितों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और पीड़िता को राहत देने के संबंध में क्या कदम उठाए गए? इस संबंध में पूरी

ललितपुर-चंदौली की घटना पर प्रदेशभर में आप का प्रदर्शन

राब्यू, लखनऊ: चंदौली और ललितपुर की घटना को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदेशभर में प्रदर्शन किया। दोनों घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सभी जिलों में जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। पार्टी की ओर से कहा गया है कि ऐसी घटनाओं पर शांत नहीं बैठ सकते। ललितपुर में सीधे-सीधे अपराध में शामिल पुलिस वालों की जांच खुद पुलिस वाले करेंगे तो न्याय मिलने में संदेह है। दोनों घटनाओं की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जानी चाहिए।

रिपोर्ट चार सप्ताह में उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

NHRC notice to UP govt over torture of woman by police in Lalitpur

INDO-ASIAN NEWS SERVICE

NEW DELHI, 7 MAY

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Uttar Pradesh government over the reported stripping and assault of a woman by police personnel in Lalitpur.

Taking suo motu cognisance of the incident, the Commission has issued notices to the Uttar Pradesh Chief Secretary and the Director General of Police calling for a detailed report in the matter within four weeks.

The NHRC has also sought a report on action taken against the responsible police officer and any relief granted to the victim by the authorities. Reportedly, the woman was working as a domestic help at the residence of a police officer and was beaten on the allegations of a theft in the house.

"The Commission has observed that the contents of the media reports, if true, raise serious issues of violation of human right to the victim. The Police Officer and his family have not only misused their position but also subjected the victim to physical torture and cruelty", said the commission in a statement.

Reportedly, on May 2, the victim was locked in a room by the wife of the police officer who came along with a lady Inspector and started interrogating her regarding a theft in the house.

"Besides beating her brutally, they also subjected her to water cannon and electric shocks to force her accept the allegations. Later, sensing that the matter may snowball into a controversy, she was called to the Mehrauli police station where the police personnel tried to project the matter as a dispute with her husband and also initiated action against him for disturbing peace", said the NHRC.

ललितपुर की घटना को लेकर एनएचआरसी ने भेजा नोटिस

लखनऊ (एसएनबी)। ललितपुर जिले के अधिकारी और उसका परिवार अपने प्रभाव
महरोली पुलिस थाने में चोरी के शक में महिला की पुलिस द्वारा पिटाई की घटना को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

मुख्य सचिव और डीजीपी से
मांगा जवाब

चोरी के शक में पुलिस ने थाने
में निर्ममता से की थी पिटाई

का दुरुपयोग कर शारीरिक चोट पहुंचाने और क्रूरता के दोषी हैं।

आयोग ने मीडिया की उन खबरों

ने सख्त रुख अख्तियार किया है। एनएचआरसी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस देकर पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की है। दोषी पुलिसकर्मियों पर लिए गये एक्शन और पीड़िता को राहत देने के बारे में जानकारी मांगी है। आयोग ने नोटिस में कहा कि यदि इस बारे में मीडिया में आई खबरों में सत्यता है तो यह पीड़िता के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मामला है। पुलिस

का संज्ञान लिया है जिसमें बताया गया था कि 2 मई को पुलिस अधिकारी की पत्नी ने चोरी के शक में घरेलू काम करने वाली महिला को घर में कैद कर लिया था। उसके पुलिस अधिकारी पति ने महिला इंस्पेक्टर को साथ लाकर पीड़िता से चोरी के सामान के बारे में पूछताछ की। उसने पीड़िता की बुरी तरह पिटाई की और चोरी कबूल करने के लिए उस पर पानी की धार छोड़ी और विजली के शॉक दिए। जैसे ही यह मामला सुर्खियों में आया पुलिस अधिकारी ने पीड़िता को थाने पर बुलाया और इस प्रकरण को पीड़िता और उसके पति के बीच का विवाद करार देने लगे। दोनों के खिलाफ शांतिभंग की आशंका में कार्रवाई कर दी। आयोग ने इस पूरे प्रकरण को वेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी से चार हफ्ते के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई के बारे में अवगत कराने का आदेश दिया है।

{ RAPE BY S.H.O. }

Lalitpur victim's mother recounts horror

**Shiv Sunny and
Haidar Naqvi**

letters@hindustantimes.com

LALITPUR AND KANPUR: "I feel safer," the 13-year-old girl said from somewhere inside the tiny dark room, a sizeable portion of which is occupied by large sacks stuffed with straw.

"You watch, I'll be able to fight," a brief pause later she adds, the firmness in her voice

palpable.

After spending five days under the protection of the Child Welfare Committee (CWC), the survivor of the Lalitpur gang rape case was escorted home by a bunch of police personnel in two multi-utility vehicles. Along with the child was her mother who was allowed to be by her side in the CWC's shelter.

While the mother tried to set the chaotic little house in order on

Saturday afternoon, and tended to her seven other younger children, the girl went into a dark corner of the house, refusing to emerge. "She has only been crying all through. I am trying to make her forget what happened, but she keeps getting reminded of it," said the mother.

The entire Pali police station staff was transferred on May 3 after it emerged that the girl was kidnapped and gang raped for

LALITPUR VICTIM

"Just because you have a powerful government job, you do not get a right over our bodies," she added.

For now, the SHO, four gang rape suspects, and the survivor's aunt — accused of abetting the child's abduction — have been arrested. While there are five men accused of rape, the mother is particularly angry with the SHO. "The police are known to recover bodies from under water. Here, no one even cared to trace my living daughter for over a week."

She said that her complaints about a similar case involving her daughter in November 2021 went unheeded. This attitude, she said, created the latest situation where the girl was kidnapped and repeatedly raped.

In the previous case being referred to by the mother, she told the court that her daughter was allegedly gang raped by two men when she was visiting the fields to relieve herself on November 7. The mother alleged that her child was gang raped at knife point by Chandan Aharwar and Mahendra Chaurasia — local villagers who

are also accused in the latest case.

"They approached the local police, but the SHO refused to register an FIR and didn't get the child medically examined," the family's lawyer, Hardayal Singh Lodhi, summed up the complaint.

On November 24, the mother approached the court to file an FIR. Her complaint named not only the rape suspects, but accused the SHO of being hand-in-glove with the alleged assaulters.

The court sought the police's response on the allegations. In his response to the court, a copy of which is with HT, a sub-inspector said no evidence was found in support of the allegations and accused the child's mother of being a "habitual" complainant. "Based on this response, the court rejected our appeal for an FIR. But, as per procedure, it asked for the girl's statement to be recorded in court on April 25," said Lodhi.

Amid all this, both parties filed additional complaints against each other.

"The child's mother had falsely implicated my older son (Jagannath) too of rape, nine years ago.

Jagannath spent time in jail and was freed only after the woman's black and white photograph was paid ₹50,000," said the father of Raj Bhadauri, who was in jail in the latest case. The police could not confirm his claim.

A case was also filed by the survivor against her aunt and others for complicity in "fake cases" against the child was misleaded by that FIR," said the court.

The woman's lawyer, Nikhil Pathak, said that none of any such black and white photographs.

Nikhil Pathak, an independent of police, said that he has been forming the complaints against the family. The court is probing why another gang rape case was not reported.

Ahead of the court's judgment in court, the girl was abducted on May 3.

Two senior police officers are to the probe said that they will maintain anonymity that the girl revealed the SHO's involvement with the alleged assaulters during the period of her

Rajasthan vs UP cops plays out in Noida over journalist's arrest

Obstructed By UP Police, Say Dungarpur Cops

TIMES NEWS NETWORK

Jaipur/Udaipur/Noida: A high-voltage drama took place on Saturday morning when a team of Rajasthan's Dungarpur district police arrived in Noida with a warrant to arrest News18 anchor Aman Chopra but returned empty-handed, thanks to what it called "obstruction" by local police.

Dungarpur SP Sudhir Joshi said it was for the second time that the Noida police "obstructed" his team and kept them waiting to allow the accused to flee from his house.

"The UP Police asked our team of 12 cops, led by an ASP-rank officer, to first

BJP calls Raj CM Gehlot modern-day 'Aurangzeb' over TV scribe house 'raid'

Rajasthan BJP has termed the state police "raid at the residence of anchor Aman Chopra a Congress-sponsored attempt to suppress the freedom of speech in India". "CM Ashok Gehlot, who is a self-proclaimed Gandhian, has damaged principles and values of the Constitution by attacking a journalist for showing the truth. It would not be an exaggeration to call him a modern-day 'Aurangzeb' for acting against the majority community to appease its core vote bank," said Satish Poonia, BJP state president. **TNN**

come to the police station with them. The team then went to the police station in Noida and showed them the arrest warrant and case details. When the team returned to Chopra's flat, he couldn't be found," the SP said, adding that the local police had done the same thing with his team earlier in the week too.

Countering the Dungarpur SP's claim, ACP-2 Central Noida Yogendra Singh said: "A team from Rajas-

than Police had come to the Bistrakh police station around 3pm with the non-bailable warrant of Aman Chopra, who resides in Arihant Apartments. They completed the legal procedure and two of our personnel accompanied them and went to Chopra's house. His house was locked, following which they pasted the warrant outside and left."

Singh further said, "They themselves came to the police station in order to

make the entry and complete the legal procedure. We didn't have any idea about any team coming. We have their entry in our books, which is of 3pm," the ACP said.

The Rajasthan Police said that an FIR was registered against Chopra at the Bichhiwara police station under IPC sections 295A (deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs), 153A (promoting enmity between different groups) and 124A (sedition), along with different provisions of the IT Act on April 23.

The FIR was filed after Chopra in his show had allegedly claimed that a centuries-old temple in Alwar was razed to avenge a demolition drive that took place in Delhi's Jahangirpuri.

Full report on www.toi.in

BBMCH MEDICO'S DEATH

Family seeks CBI probe

POST NEWS NETWORK

Bolangir, May 7: Family members of Nishant Kumar, a first year MBBS student who died after allegedly falling off the hostel rooftop, have demanded a probe by the CBI Saturday.

Alleging suicide due to excess ragging, mental and physical torture by seniors and professors, Nishant's father Krishan Kumar sought the intervention of the central agency in a letter to Prime Minister Narendra Modi and the NHRC.

In the letter, Nishant's father revealed how juniors are tortured in the prestigious institute by seniors and professors. The lecturers here force juniors to write the laboratory manuals of senior students. Furthermore, the juniors who have good handwriting are

tortured to do all the homework of the seniors. Instead of taking action on ragging, the professors take the side of the seniors and make fun of juniors, he alleged.

The seniors have created WhatsApp groups and call the juniors for ragging late in the night. The students are sexually harassed and threatened with dire consequences if they dare to report the incident.

Juniors are assaulted if they see the seniors eye to eye. They are made to clean the college stadium for hours, but not allowed to play. They are verbally abused with filthy language.

Nishant's father has sent a copy of his WhatsApp chats revealing about the torture to the PMO and the NHRC. He had earlier sought intervention of Bolangir SP.

NHRC seeks report over detention of juveniles

TIMES NEWS NETWORK

Bhopal: The National Human Rights Commission has taken suo motu cognizance of a media report which stated that four juveniles have been illegally detained in police custody on suspicion of theft in Tikamgarh district of MP since April 30.

NHRC stated the media reports also reveal that the juveniles have been chained by the police and there are injuries on their bodies indicating that they are being subjected to torture by the police.

The commission has observed that the contents of the media report, if true, amount to gross violation of the victims who are children. The juveniles cannot be detained in a police station, it stated. Even if the police believed that they committed a crime they should have been given in the care of juveniles police unit or a designated child welfare police officer. The juveniles should have been produced before the Juvenile Justice Board within 24 hours of their detention and they are not supposed to be chained in any case, the commission said.

NHRC notice on honour killing

Takes suo motu cognizance of man's murder by wife's brother

#NEWDELHI

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday took suo motu cognizance of the murder of a 25-year-old man by his wife's brother and another person in Hyderabad in a suspected "honour killing".

It has issued notices to the state chief secretary and director general of police, calling for a detailed report in the matter within four weeks.

The chief secretary has been asked to submit a report whether the state government has any policy to prevent such incidents of "honour killing" in cases of inter-caste or inter-religion marriage.

The DGP has been asked to inform the present status of the investigation in the case, steps taken to safeguard the

IANs



wife of the victim and his family members.

"The Commission would also like to know whether there were any lapses on the part of the police authorities in this case if so, what action has been taken against the guilty," the NHRC said in a statement.

"Police has stated that the brother of the girl was opposed to her inter-faith marriage," it noted. **IANs**

Poser to UP on stripping

#NEWDELHI

The NHRC has issued a notice to the Uttar Pradesh government over the stripping and assault of a woman by police in Lalitpur. **IANs**

Owaisi condemns killing

#HYDERABAD

AIMIM president Asaduddin Owaisi has condemned the alleged honour killing of a Hindu man by the relatives of his Muslim wife in Hyderabad stating that that Nagraju's murder is against Islam. **IANs**